हितों के टकराव की समस्या एवं उसका समाधान को विस्तारपूर्वक समझाइए।

परिचय

सामाजिक नीति (Social Policy) का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा समान अवसर सुनिश्चित करना है। किंतु समाज में विभिन्न वर्गों, संस्थाओं एवं संगठनों के हित अलग-अलग होते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं के हित एक-दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तब हितों का टकराव (Conflict of Interest) उत्पन्न होता है। यदि इसका उचित समाधान न किया जाए तो नीति निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हितों के टकराव (Conflict of Interest) का अर्थ

हितों का टकराव वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समूह के व्यक्तिगत, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक हित सार्वजनिक हित या सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों से टकराने लगते हैं।

उदाहरण:

यदि किसी औद्योगिक परियोजना से रोजगार बढ़ता है, लेकिन उससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है, तो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच हितों का टकराव उत्पन्न होता है।

हितों के टकराव के कारण

1. संसाधनों की कमी – सीमित संसाधनों के कारण विभिन्न समूहों में प्रतिस्पर्धा।

2. आर्थिक असमानता – अमीर एवं गरीब वर्गों के हित अलग-अलग होना।

3. राजनीतिक दबाव – राजनीतिक दल या प्रभावशाली समूह अपने हितों को प्राथमिकता देना।

4. व्यक्तिगत स्वार्थ – व्यक्तिगत लाभ को सार्वजनिक हित से ऊपर रखना।

5. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता – विभिन्न समुदायों की आवश्यकताएँ एवं प्राथमिकताएँ अलग होना।

6. क्षेत्रीय असमानता – विभिन्न क्षेत्रों की विकास संबंधी आवश्यकताओं में अंतर।

7. अस्पष्ट नीतियाँ – नीति में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव।

हितों के टकराव की समस्याएँ

1. नीति निर्माण में बाधा

विभिन्न हितों के कारण सर्वसम्मति बनाना कठिन हो जाता है।

2. सामाजिक असंतोष

यदि किसी एक वर्ग के हितों की उपेक्षा होती है तो विरोध, आंदोलन एवं असंतोष उत्पन्न हो सकता है।

3. भ्रष्टाचार एवं पक्षपात

व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के कारण निष्पक्ष निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

4. संसाधनों का असमान वितरण

कुछ वर्गों को अधिक लाभ मिलता है जबकि अन्य वर्ग वंचित रह जाते हैं।

5. विकास कार्यों में विलंब

विवादों एवं विरोध के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा हो जाता है।

6. सामाजिक न्याय प्रभावित होना

कमजोर एवं वंचित वर्गों के अधिकारों की अनदेखी हो सकती है।

हितों के टकराव का समाधान

1. पारदर्शिता (Transparency)

नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया को खुला और पारदर्शी बनाया जाए।

2. जनसहभागिता (Public Participation)

सभी हितधारकों (Stakeholders) को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

3. निष्पक्ष एवं उत्तरदायी प्रशासन

निर्णय सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर लिए जाएँ।

4. स्पष्ट कानून एवं नियम

हितों के टकराव से बचने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान बनाए जाएँ।

5. अनुसंधान एवं तथ्य आधारित निर्णय

वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विश्वसनीय आँकड़ों के आधार पर नीति बनाई जाए।

6. संवाद एवं मध्यस्थता

विभिन्न पक्षों के बीच चर्चा, वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा सहमति बनाई जाए।

7. नैतिक मूल्यों का पालन

ईमानदारी, निष्पक्षता, जवाबदेही एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जाए।

8. नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन

नीतियों के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएँ।

भारतीय संदर्भ में उदाहरण

भूमि अधिग्रहण में किसानों और उद्योगों के हितों का टकराव।

वन संरक्षण और खनन परियोजनाओं के बीच संघर्ष।

जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद।

विकास परियोजनाओं एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता।

हितों के टकराव से बचने के उपाय

सार्वजनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

सभी हितधारकों के साथ परामर्श करना।

पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन व्यवस्था अपनाना।

भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण।

न्यायपूर्ण एवं समावेशी नीतियों का निर्माण।

संवैधानिक मूल्यों एवं मानवाधिकारों का पालन।

निष्कर्ष

हितों का टकराव किसी भी समाज एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वाभाविक है, लेकिन इसका उचित प्रबंधन आवश्यक है। पारदर्शिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष प्रशासन, अनुसंधान आधारित नीति निर्माण तथा नैतिक मूल्यों के पालन से हितों के टकराव को कम किया जा सकता है। इससे सामाजिक नीति अधिक प्रभावी, न्यायसंगत एवं जनकल्याणकारी बनती है।

संदर्भ ग्रंथ (References)

1. Friedlander, Walter A. (1977). Concepts and Methods of Social Work. Prentice Hall of India.

2. Titmuss, Richard M. (1974). Social Policy: An Introduction. George Allen & Unwin.

3. Kulkarni, P. D. (1979). Social Policy and Social Development in India. Association of Schools of Social Work in India.

4. Dubey, S. N. (2015). Social Work: An Integrated Approach. New Royal Book Company.

5. गोयल, एस. एल. एवं गोयल, राकेश. (2018). सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक नीति. आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।

6. सिंह, आर. बी. एस. (2016). समाज कार्य एवं सामाजिक नीति. रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।